

'Improving basic infra key to building smart cities'

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: Basic requirements like sewage management, pollution control, infrastructure development, alternative transport solutions should be the main focus before we can opt for smart solutions, said Jaipur mayor Ashok Lahoty while addressing the 'Smart & Digital Rajasthan' summit here on Wednesday.

"Now, we cannot talk about using smart technologies. We don't have the basic infrastructure. Our overhead electric wires are overlapping and hanging dangerously. The priority is to put them underground. Similarly, we don't have enough dustbins but we are talking about issuing tenders for smart chips in the dustbins. We should know what are priorities are, which is the basic infrastructure. There after we can think of smart technologies," said Lahoty.

The concepts of smart city development cannot be imported from foreign countries and adopted in India due to the diverse demographic, geographic and financial constraints of the country, he added.

Extending further on the unique local situation, executive vice president of Indo-American Chamber of Commerce Lalit Bhasin said that the definition of smart city depends on the level of development of a particular city.

"Smart cities need to be able to provide walkable areas, promote open spaces, offer transportation options as well as citizen-friendly and cost-effective governance. The willingness to change and the aspirations of the citizens are also important," added Bhasin.

Rajasthan and CII-IGBC has undertaken some joint actions to facilitate smart city projects throughout the state.

DNA

JAIPUR | THURSDAY, MARCH 15, 2018

Smart & Digital Raj Summit

Jaipur: Basic components of development among others needs to be the focus of development before we can opt for smart solutions.

This was stated by Mayor Ashok Lahoti, he was addressing the 'Smart & Digital Rajasthan Summit & Expo 2018.

**स्मार्ट एंड डिजिटल
राजस्थान समिट और
एक्सपो 2018**

शहरों में पहले बेतरतीब बसावट, नाली-पानी-परिवहन स्मार्ट होंगे, तभी बन सकेगी स्मार्ट सिटी : लाहोटी

पॉलिटिकल रिपोर्टर, जयपुर | मेयर अशोक लाहोटी ने कहा कि स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट अच्छा है। शहर स्मार्ट बनने चाहिए। हकीकत यह है कि हर शहर की भौगोलिक स्थिति, टोपोग्राफी और विरासत अलग-अलग है। विदेशों के कॉन्सेप्ट को कॉपी करके शहर स्मार्ट नहीं बनाए जा सकते। यहां भी स्मार्ट सिटी की बातें ज्यादा हो रही हैं। आज भी एक-एक शहर में 2000 कॉलोनियों के पास पट्टे नहीं। बेतरतीब

बसावट है। न सीवरेज तंत्र स्मार्ट है, न परिवहन तंत्र। पानी-प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम भी ठीक नहीं है। ऐसे में स्मार्ट सॉल्यूशंस तभी लागू होंगे जब स्मार्ट के मूल घटकों पर पहले से बेहतर काम होगा। लाहोटी एक होटल में आयोजित 2 दिवसीय स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018 को संबोधित कर रहे थे। इसमें सीएम वसुंधरा राजे और यूडीएच मंत्री को आना था, लेकिन व्यस्तताओं

के कारण नहीं आ पाए। इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) द्वारा यूडीएच एवं 'द गिल्ड' के सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डॉ. ललित भसीन ने कहा लोग स्मार्ट होंगे तो ही शहर स्मार्ट बनेंगे। यूएस कमर्शियल सर्विसेज की ऐलीन ब्रोव नेंडी ने कहा कि भारत में बढ़ता शहरीकरण नया खतरा है। पहले शहरों में स्वच्छ जल, बिजली व परिवहन जरूरी है।

स्मार्ट और डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो में एक्सपर्ट ने कहा- फिजिकल से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी अहम।

100 शहरों में अकेला जयपुर जो बन सकता है पूरी तरह स्मार्ट

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इनमें राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर व अजमेर शामिल हैं। लेकिन इस दौड़ में जयपुर सबसे आगे है। वजह इस शहर की प्लानिंग के साथ की गई बसावट है। साथ ही खूबसूरत आर्किटेक्चर जो हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। जबकि जयपुर में बाजार, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और अस्पताल की बसावट शहर के बीचोबीच है। ये बातें होटल मैरियट में शुरू हुए स्मार्ट और डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो में एक्सपर्ट ललित भसीन ने कही।

सिंगापुर की तर्ज पर जयपुर को ग्रीन सिटी में डेवलप करेंगे



स्मार्ट सिटी पिकसिटी की खूबसूरती खत्म नहीं करेगा। क्योंकि जयपुर शहर को महाराजा स्वर्ण जयसिंह ने प्लानिंग के साथ

बसाया है। इसलिए भी स्टेट गवर्नमेंट को बाकी शहरों की तुलना में सिर्फ आधारभूत सुविधाओं को अपग्रेड करने पर ध्यान देना होगा। सिंगापुर तर्ज पर जयपुर में काम किया जाएगा।

-**वी. सुरेश**, प्रेजीडेंट, गुड्स गवर्नेंस इंडिया फाउंडेशन

वॉशिंगटन के अचीवमेंट को अडॉप्ट करें, बेहतर होगा



2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने 100 शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। इस तरह के कॉन्फ्रेंस से प्राइवेट फर्म के भी

आइडियाज मिलेंगे। मगर जयपुर अकेला ऐसा शहर है जो पूरी तरह स्मार्ट बन सकता है। क्योंकि यहां हिस्टोरिकल डेवलपमेंट काफी प्लानिंग के साथ किया गया है।

-**ललित भसीन**, सी. वाइस प्रेजीडेंट ऑफ नेशनल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स

फिजिकल सिक्योरिटी से ज्यादा अहम साइबर सिक्योरिटी



फिजिकल सिक्योरिटी पर ध्यान है मगर साइबर सिक्योरिटी पर किसी का नहीं। उदाहरण के लिए आधार कार्ड सालों

से बना रहे हैं, अब जाकर लोगों को इसकी डेटा सिक्योरिटी की चिंता हो रही है। क्योंकि फिजिकल सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा साइबर सिक्योरिटी खतरनाक है।

-**रविंद्र पातल सिंह**, डायरेक्टर, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सिटीज

राजस्थान पत्रिका

जयपुर. गुरुवार . 15.03.2018

‘स्मार्ट उपायों से पहले वैकल्पिक साधन करने होंगे विकसित’

स्मार्ट और डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो-2018

जयपुर @ पत्रिका. स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पहले हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, आधारभूत विकास, परिवहन के वैकल्पिक साधन विकसित करने होंगे। यह कहना है महापौर अशोक लाहोटी का। वे बुधवार

को यहां होटल में ‘स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018’ के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे।

दो दिवसीय समिट का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) की ओर से राज्य सरकार एवं ‘द गिल्ड’ के सहयोग से किया जा रहा है। शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग है।

महापौर बोले... कैसी स्मार्ट सिटी, दो हजार कॉलोनियों में नहीं सीवरेज सिस्टम

स्मार्ट और डिजिटल राजस्थान समिट एण्ड एक्सपो- 2018 शुरू



व्यक्तो/नवज्योति, जयपुर

महापौर अशोक लाहोटी ने विदेशों की स्मार्ट सिटी की अवधारणा को यहां ज्यों का त्यों थोपने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैसी स्मार्ट सिटी, यहां की दो हजार कॉलोनियों में सीवरेज सिस्टम नहीं है। हमारी भौगोलिक, डेमोग्राफिक और आर्थिक स्थितियां विदेशों से भिन्न हैं। स्मार्ट सोल्यूशंस को लागू करने से पहले हमें सीवरेज, प्रदूषण निंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर

ध्यान देना होगा। लाहोटी होटल मैरियट में 'स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की करना था, लेकिन व्यस्तता के चलते वे समिट में नहीं पहुंच सकी। मेयर ने कहा कि जयपुर शहर स्थापना से ही स्मार्ट है, इसे बरकरार रखने की जरूरत है। दो दिवसीय इस समिट का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) की ओर से किया जा रहा है।

यह बोले एक्सपर्ट

- आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डॉ. ललित भसीन ने स्वागत भाषण में बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की इच्छा, नागरिकों की महत्वाकांक्षा से उस शहर की स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है। स्मार्ट सिटी में ऐसे स्थान आवश्यक हैं जहां लोग पैदल चल सकें, खुली जगह हो, परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध हों।
- अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की कमर्शियल काउंसलर ऐलीन क्रोव ने डी ने कहा कि भारत के स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएं हैं। अनेक अमेरिकी कम्पनियां स्मार्ट सिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्मार्ट और नए तरह के सोल्यूशन्स उपलब्ध कराती हैं।
- आईजीवीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने बताया कि स्मार्ट सिटीज के जरिए बिजली की खपत में कमी लाई जा सकती है, लाइटिंग का लोड कम हो सकता है और पानी की 40 से 50 प्रतिशत तक बचत हो सकती है। इसके लिए ब्राउनफोल्ड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए ताकि मौजूदा शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जा सके।
- जे.मोहनको कस्ट्रक्शंस के मैनेजिंग पार्टनर जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि बेहतर परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षण व्यवस्था, अफोर्डेबल हाउसिंग एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सुदृढ़ लिंकेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मूल आवश्यकताएं हैं।

दैनिक नवज्योति

जयपुर, गुरुवार, 15 मार्च 2018

अवैध निर्माण स्मार्ट सिटी में बाधक स्मार्ट और डिजीटल राजस्थान समिट में पैनल डिस्कशन

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

स्मार्ट सिटीज इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. ए. रविन्द्र ने कहा कि अवैध निर्माण, बढ़ते अपराध और तेजी से बढ़ता व्यावसायीकरण स्मार्ट सिटी के विकास में बड़े बाधक हैं। स्मार्ट सिटी को भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना जरूरी है।

इसके रखरखाव में नागरिकों का व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। स्मार्ट और डिजीटल राजस्थान समिट एण्ड एक्सपो 2018 में बुधवार को बिल्डिंग्स द सिटीज ऑफ टुमारो- स्मार्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्मार्टर टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीजन्स पर पैनल चर्चा में रविन्द्र ने यह बात कही। इस चर्चा में जॉनसन कंट्रोल्लेस

इंडिया के जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत बापट ने कहा कि वर्ष 2050 तक 70 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या शहरों में रहने लगेगी। स्मार्ट सिटीज के विकास पर भारत लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा। जीआइएफटी सिटी के चीफ आर्किटेक्ट्स और प्लानर राजेश फड़के ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि इंटिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर काम किया जाए, जिसमें आंतरिक परिवहन, जल की सुविधा, सैटेलाइट कूलिंग सिस्टम और ऑटोमैटेड वेस्ट कलक्शन तथा सेग्रिगेशन प्लांट हों। इसके अलावा आग से बचाव के उपाय और 24 घंटे कार्य करने वाला सर्विलांस सिस्टम भी होना चाहिए।

डिजीटल नक्शा तैयार करना

कुशमैन एंड वेकफील्ड के डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी इंडिया आर.के. गौतम ने कहा कि स्मार्ट सिटीज के रूप में बदलने के लिए जिन शहरों को चुना गया, उनमें से ज्यादातर को इस बारे में सोचना होगा कि जब उनके शहर की जनसंख्या पांच लाख से ज्यादा हो जाएगी तो उन्हें किन सुविधाओं को अपग्रेड करना है। सेवाओं, भौतिक सम्पत्तियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर के डिजीटाइजेशन से भविष्य के लिए डिजीटल नक्शा तैयार किया जा सकता है। बाद में डिजीटल इंडिया-क्रिएटिंग नेक्सट जनरेशन पब्लिक सर्विसेज और ट्रिनिटी ऑफ स्मार्ट इकोसिस्टम्स-स्मार्ट बिल्डिंग्स स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, एंड स्मार्ट सिटीज विषयों पर भी चर्चा हुई।

स्मार्ट सिटी से पहले बेहतर पानी-बिजली सहित अन्य सुविधाएं जरूरी: लाहोटी

उद्घाटन

स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिति और एक्सपो-2018 शुभ

पंजाब केसरी/जयपुर

किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने उसमें स्मार्ट सॉल्यूशंस को लागू करने से पहले वहां की जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सबसे जरूरी है। जब तक उस शहर में सीवरेज, पानी-बिजली, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन नहीं होंगे, तब तक स्मार्ट सॉल्यूशंस को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।

ये बात बुधवार को मेयर अशोक लाहोटी ने एक होटल में आयोजित 'स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिति और एक्सपो-2018' के



एक होटल में आयोजित 'स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिति व एक्सपो-2018' उद्घाटन करते अतिथि।

उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कही।

दो दिवसीय इस समिति का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) द्वारा राजस्थान सरकार और 'द गिल्ड'

के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग प्राप्त है। इस अवसर पर आईएसीसी के एक जीव यूटिव वाइस

प्रेसीडेंट डॉ. ललित भसीन ने बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की इच्छा, नागरिकों की महत्वाकांक्षा से उस शहर को स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है। स्मार्ट सिटी में ऐसे स्थान आवश्यक हैं, जहां

लोग पैदल चल सकें। खुली जगह हो, परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध हों और नागरिकों के अनुकूल एवं किफायती प्रशासन हो। इस मौके पर अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की कमर्शियल काउंसलर, ऐलीन क्रोव नेंडी ने कहा कि भारत के स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएं हैं।

यहां शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में स्वच्छ जल, बिजली और परिवहन बेहद जरूरी हैं। अनेक अमेरिकी कम्पनियां स्मार्ट सिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्मार्ट और नए तरह के सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती हैं। भारतीय और अमेरिकी कम्पनियों के मध्य परस्पर सहयोग और बढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें स्मार्ट सॉल्यूशंस आसानी से मिल सकें।

स्मार्ट सॉल्युशन्स लागू करने से पहले मूल घटक विकसित करने होंगे : लाहोटी



मेयर अशोक लाहोटी ने बुधवार को 'स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो-2018' का उद्घाटन किया। उनके साथ आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट डॉ. ललित भसीन, यूएस कमर्शियल सर्विसेज की काउंसलर ऐलीन क्रोव नेंडी, आईजीबीसी के वी.सुरेश और जैमिनी ओबेराय समेत कई लोग मौजूद थे।

फोटो-राष्ट्रदूत

जयपुर, (कांस)। स्मार्ट सॉल्युशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा। यह बात मेयर अशोक लाहोटी ने कही।

लाहोटी बुधवार को जयपुर मैरियट में 'स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018' के उद्घाटन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विदेशों की तरह

स्मार्ट सिटी डवलपमेंट की अवधारणा को यहीं ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक, डेमोग्राफिक और आर्थिक स्थितियां अन्य देशों से भिन्न है।

अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की कमर्शियल काउंसलर, ऐलीन क्रोव नेंडी ने कहा कि भारत के स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएं हैं। भारत में शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में स्वच्छ जल, बिजली और परिवहन बेहद

जरूरी हैं। भारतीय-अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग और बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें स्मार्ट सॉल्युशन्स आसानी से मिल सकें। आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, वी.सुरेश ने बताया कि 4,452 ग्रीन प्रोजेक्ट के साथ भारत का ग्रीन फुटप्रिंट 4.79 बिलियन वर्ग फुट है। स्मार्ट सिटीज के जरिए बिजली की खपत में कमी लाई जा सकती है, लाइटिंग का लोड कम हो सकता है और पानी की 40 से 50 प्रतिशत तक बचत हो सकती है।

स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व मूल घटकों को विकसित करना होगा : मेयर

‘स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो-2018’ का उद्घाटन

जयपुर (कांग्रेस)। स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा। यह कहना है मेयर अशोक लाहोटी का। लाहोटी बुधवार को जयपुर मैरिच में ‘स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018’ के उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रहे थे। दो दिवसीय इस समिट का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएससी) द्वारा राजस्थान सरकार एवं ‘द गिल्ड’ के सहयोग से किया जा रहा है।

इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग प्राप्त है। मेयर ने आगे कहा कि विदेशों की तरह स्मार्ट सिटी डवलपमेंट की अवधारणा को यहां ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक, डेमोग्राफिक और आर्थिक स्थितियां अन्य देशों से भिन्न हैं।



आईएससी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट, डॉ. ललित धर्सी ने स्वागत भाषण में बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की इच्छा, नागरिकों की महात्वाकांक्षा से उस शहर को स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है।

जे. मोहनको कंस्ट्रक्शन्स के मैनेजिंग पार्टनर, जैमिनी डवेरॉय ने कहा कि बेहतर परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षण व्यवस्था, अग्रेसिव बल हाउसिंग एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सुदृढ़ लिंकेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मूल आवश्यकताएं हैं। यह

अत्यंत आवश्यक है कि निवेशक इन प्रोजेक्ट्स में रुचि दिखाएं। आईएससी जयपुर डेस्क के चेयरमैन संजीव बाली ने इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित किया। जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया के जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत

वापट ने कहा कि वर्ष 2050 तक 70 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या शहरी में रहने लगेगी। स्मार्ट सिटीज के विकास पर भारत लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा।

जीआइएफटी सिटी के चीफ ऑफिकेक्ट्स और प्लानर राजेश फडके ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर काम किया जाए, जिसमें आंतरिक परिवहन, जल की सुविधा, सैटेलाइट ड्रिलिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड वेस्ट कलक्शन तथा सेपिगेशन प्लांट हों। इसके अलावा आग से बचाव के उपाय और 24 घंटे कार्य करने वाला सर्विलांस सिस्टम

भी होना चाहिए। स्मार्ट सिटीज इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. ए. रविन्द्रा ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना जरूरी है। स्मार्ट सिटीज के रखरखाव में नागरिकों का व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवैध निर्माण, बढ़ते अपराध और तेजी से बढ़ता व्यवसायीकरण स्मार्ट सिटी के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं। बाद में डिजिटल इंडिया-क्रिएटिंग नेक्स्ट जनरेशन पब्लिक सर्विसेज और द ट्रिनिटी ऑफ स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर-स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, एंड स्मार्ट सिटीज विषयों पर भी चर्चा हुई।

भारत में स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएं

इस अवसर पर अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की कमर्शियल काउंसलर पैलोन क्रॉय नेंडी ने कहा कि भारत में स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएं हैं। आईबीसी की पॉलिटी एंड एडवोकैसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने बताया कि 4,452 ग्रीन प्रोजेक्ट के साथ भारत का ग्रीन फुटप्रिंट 4.79 बिलियन वर्ग फुट है। स्मार्ट सिटीज के जरिए बिजली की खपत में कमी लाई जा सकती है, लाइटिंग का लोड कम हो सकता है और पानी की 40 से 50 प्रतिशत तक बचत हो सकती है।

जागरूक टाइम्स जयपुर, गुरुवार 15 मार्च, 2018



स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व मूल घटकों को विकसित करना होगा : लाहोटी

जयपुर। स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा। यह बात जयपुर के मेयर, अशोक लाहोटी ने कही है। वे आज जयपुर मैरियट में 'स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018' के उद्घाटन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। दो दिवसीय इस समिट का आयोजन 'इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी)' द्वारा राजस्थान सरकार एवं 'द गिल्ड' के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग

प्राप्त है। जयपुर मेयर ने आगे कहा कि विदेशों की तरह स्मार्ट सिटी डवलपमेंट की अवधारणा को यहाँ ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक, डेमोग्राफिक और आर्थिक स्थितियाँ अन्य देशों से भिन्न हैं। इस अवसर पर आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट, डॉ. ललित भसीन ने स्वागत भाषण में बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की इच्छा, नागरिकों की महत्वाकांक्षा से उस शहर की स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है। स्मार्ट सिटी में ऐसे स्थान आवश्यक हैं जहाँ लोग पैदल चल सकें, खुली जगह हो, परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध हों और

नागरिकों के अनुकूल एवं किफायती प्रशासन हो। इस अवसर पर अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की कमर्शियल काउंसलर, ऐलीन क्रोव नेंडी ने कहा कि भारत के स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएँ हैं। भारत में शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में स्वच्छ जल, बिजली और परिवहन वेहद जरूरी हैं। अनेक अमेरिकी कम्पनियाँ स्मार्ट सिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्मार्ट और नए तरह के सॉल्यूशन्स उपलब्ध कराती हैं। भारतीय और अमेरिकी कम्पनियों के मध्य परस्पर सहयोग और बढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें स्मार्ट सॉल्यूशन्स आसानी से मिल सकें।

दैनिक
कंचन केसरी

जयपुर, गुरुवार 15 मार्च 2018

शहर के विकास के लिए सुविधाओं का विस्तार

कंचन केसरी

जयपुर/कास। स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा। यह विचार जयपुर के मेयर, अशोक लाहोटी ने कही है। वे स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018 के उद्घाटन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे।

दो दिवसीय इस समिट का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) द्वारा राजस्थान सरकार एवं द गिल्ड के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग प्राप्त है।

स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एवं एक्सपो 2018 का शुभारंभ

जयपुर। स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा। यह बात जयपुर के मेयर, अशोक लाहोटी ने कही है। वह मंगलवार को जयपुर मैरियट में 'स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018' के उद्घाटन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। दो दिवसीय इस समिट का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) द्वारा राजस्थान सरकार एवं 'द गिल्ड' के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग प्राप्त है। जयपुर मेयर ने आगे कहा कि विदेशों की तरह स्मार्ट सिटी डवलपमेंट की अवधारणा को यहां ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक, डेमोग्राफिक और आर्थिक स्थितियां अन्य देशों से भिन्न हैं।

इस अवसर पर आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट, डॉ. ललित भसीन ने स्वागत भाषण में बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की इच्छा, नागरिकों की महत्वाकांक्षा से उस शहर की स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है। स्मार्ट सिटी में ऐसे स्थान आवश्यक हैं जहां लोग पैदल चल सकें, खुली जगह हो, परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध हों और नागरिकों के अनुकूल एवं किफायती प्रशासन हो। इस अवसर पर अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की कमर्शियल काउंसलर, ऐलीन क्रोव नेंडी ने कहा कि भारत के स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएं हैं। भारत में शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में स्वच्छ जल, बिजली और परिवहन बेहद जरूरी है। अनेक अमेरिकी कम्पनियां स्मार्ट सिटी डवलपमेंट



प्रोजेक्ट्स के लिए स्मार्ट और नए तरह के सॉल्यूशन्स उपलब्ध कराती हैं। भारतीय और अमेरिकी कम्पनियों के मध्य परस्पर सहयोग और बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें स्मार्ट सॉल्यूशन्स आसानी से मिल सकें।

आईजीवीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, ची.सुरेश ने बताया कि 4,452 ग्रीन प्रोजेक्ट के साथ भारत का ग्रीन फुटप्रिंट 4.79 बिलियन वर्ग फुट है। स्मार्ट सिटीज के जरिए बिजली की खपत में कमी लाई जा सकती है, लाइटिंग का लोड कम हो सकता है और पानी की 40 से 50 प्रतिशत तक बचत हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए ताकि मौजूदा शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जा सके। जे.मोहनको कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग पार्टनर, जैमिनी उबेरॉय ने अपने शुरूआती भाषण में कहा कि बेहतर परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षण व्यवस्था, अफोर्डेबल हाउसिंग एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सुदृढ़ लिंकेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मूल आवश्यकताएं हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि निवेशक इन प्रोजेक्ट्स में रूचि दिखाएं। आईएसीसी जयपुर डेस्क के चेयरमैन संजीव बाली ने इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व मूल घटकों को विकसित करना होगा

जयपुर। स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज प्रदूषण नियंत्रण इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा। यह बात जयपुर के मेयर अशोक लहोटी ने कही है। वे आज जयपुर मैरिथेट में स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिति और एप्रैल 2018 के अद्ययन में संबोधित कर रहे थे। दो दिवसीय इस समिति का आयोजन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी द्वारा राजस्थान सरकार एवं द गिल्ड के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन, यूटीएचड विभाग का भी सहयोग प्राप्त है। जयपुर मेयर ने आगे कहा कि विदेशों की तरह स्मार्ट सिटी डवलपमेंट की अवधारणा को यहां ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता है। भौगोलिक डेमोग्राफिक और आर्थिक स्थितियां अन्य देशों से भिन्न है।

बुलेटिन टुडे

बुधवार
14.03.2018

स्मार्ट एंड डिजिटल समिट का शुभारंभ



जगपुर। दो दिवसीय स्मार्ट एंड डिजिटल समिट का आयोजन बुधवार को होटल मेरियट में शुरू हुआ। महापौर अशोक लाहोटी व अन्य अतिथियों ने समिट का शुभारंभ किया। इंडो-अमरीकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित स्मार्ट एंड डिजिटल समिट में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। सीएम वसुंधरा राजे का भी संबोधन होगा।



जयपुर बुधवार 14.03.18

डिजिटल तकनीक से स्मार्ट बनेंगे शहर



जयपुर • आज से राजधानी जयपुर में शुरू हुआ स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट-एक्सपो 2018। एक्सपो में भविष्य के शहरों के निर्माण में स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजी की भूमिका को लेकर मंथन हो रहा है। समिट का उद्घाटन महापौर अशोक लाहोटी ने किया।